भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1296

उत्तर देने की तारीख-11/02/2026

उच्च शिक्षा का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीयकरण

1296 # श्री बृज लाल:
श्री रायगा कृष्णैया:
श्रीमती संगीता यादव:
श्री मदन राठौड़:
श्री सुभाष बराला:
श्रीमती रेखा शर्मा:
श्रीमती किरण चौधरी:
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:
श्री चुन्नीलाल गरासिया:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025 तक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम और एम्स सहित उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और कितनी अतिरिक्त क्षमता सृजित हुई है;

(ख) विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा की उपस्थिति जैसे आईआईटी/आईआईएम के परिसर स्थापित करने या विस्तार करने तथा भारत में विदेशी संस्थानों और छात्रों को आकर्षित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ग) उच्च शिक्षा के आकांक्षी विद्यार्थियों के लिए वित्तीय बाधाओं को कम करने में सरकारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का क्या प्रभाव रहा है; और

(घ) भारत की बढ़ती शैक्षिक उत्कृष्टता के संकेतक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, छात्र/संकाय आदान-प्रदान कार्यक्रमों और वैश्विक रैंकिंग में सुधार के क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार,

पंजीकृत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों (आईआईटी, आईआईएम, एम्स आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों सहित) की संख्या बढ़कर 1,213 हो गई, कॉलेजों की संख्या बढ़कर 46,624 हो गई और स्टैंड-अलोन संस्थान बढ़कर 12,543 हो गए।

वर्ष 2014 से, 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), 8 केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू), 8 भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), 1 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और 12 नए एम्स स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त , बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अनुसरण में, सरकार ने 11,828.79 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरुपति), केरल (आईआईटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आईआईटी भिलाई), जम्मू और कश्मीर (आईआईटी जम्मू) और कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) में स्थापित पांच नए आईआईटी के अनुसंधान पार्क के निर्माण सहित शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे की क्षमता के विस्तार को अनुमोदित किया है जिससे अतिरिक्त 6,500 छात्रों के लिए शिक्षा की सुविधा होगी।

(ख): सरकार ने भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विदेशों में परिसर स्थापित करने की सुविधा प्रदान की है जिसमें ज़ंज़ीबार, तंज़ानिया में आईआईटी मद्रास परिसर; अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली परिसर; और दुबई में आईआईएम अहमदाबाद परिसर शामिल है । विदेशी संस्थानों को आकर्षित करने के लिए, सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम 2023 के तहत भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एफएचईआई) की स्थापना को सक्षम बनाया है। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय (यूके), गुरुग्राम कैंपस ने आशय पत्र (एलओआई) के साथ-साथ अनुमोदन पत्र (एलओए) के अनुदान के बाद सत्र 2025-26 के लिए अपना शैक्षणिक संचालन शुरू कर दिया है। आस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के एफएचईआई को बेंगलुरू (कर्नाटक), दिल्ली एनसीआर, मुंबई (महाराष्ट्र) और चेन्नई (तमिलनाडु) सहित भारत में विभिन्न स्थानों पर अपने परिसर स्थापित करने के लिए 13 आशय पत्र जारी किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) विनियम 2022 के तहत, यूके, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी आयरलैंड के 5 विश्वविद्यालयों को गिफ्ट सिटी एसईजेड, गांधीनगर, गुजरात में अपतटीय शाखा परिसरों के संचालन के लिए अनुमोदन दिया गया है। इन 5 विश्वविद्यालयों में से, डीकिन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया ने अपने पाठ्यक्रम शुरू किए।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2018 में 'स्टडी इन इंडिया' योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य भारत को किफ़ायती लागत पर विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग स्टडी इन इंडिया (एसआईआई) पोर्टल है, जो सभी आने वाले विदेशी छात्रों के लिए

प्रवेश और वीजा आवेदनों के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन है और भारतीय उच्चतर शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने हेतु एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा सितंबर 2022 में 'भारत में एचईआई में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के लिए दिशानिर्देश' जारी किए गए थे। यूजीसी ने "यूजीसी (जुड़वां, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों को प्रस्तावित करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग) विनियम, 2021 भी जारी किए हैं, जो छात्रों को भारतीय और विदेशी दोनों विश्वविद्यालयों से अपने कार्यक्रमों के कुछ हिस्सों को करने की अनुमति देते हैं, जिससे शैक्षणिक और अनुसंधान उत्कृष्टता के साथ-साथ छात्रों और शिक्षकों की गतिशीलता भी होती है।

(ग): शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और इसके सुधार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कार्य करती हैं। सरकार हाशिए पर रहने वाले वर्गों के छात्रों सहित छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। स्लॉट की संख्या, प्रस्तावित सहायता और पात्रता मानदंड सहित इन योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:

क्रं.सं.	**मंत्रालय/विभाग**	**वेबसाइट लिंक**
1	उच्चतर शिक्षा विभाग	https://www.education.gov.in/en/scholarships-education-loan-0
2	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	https://dsel.education.gov.in/en/scheme/nmmss
3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	https://www.ugc.gov.in/Home/student_Corner
4	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	https://www.aicte.gov.in/bureaus/rifd/Scholarship-Schemes
5	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	https://socialjustice.gov.in/schemes
6	जनजातीय कार्य मंत्रालय	https://tribal.nic.in/ScholarshiP.aspx
7	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=2&ls_id=661&lid=823
8	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	https://dst.gov.in/inspire-scheme-innovation-science-pursuit-inspired-research

छात्रवृत्ति योजनाएं सभी छात्रों के लिए देश भर में हैं, ताकि छात्र योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार योजना का लाभ उठा सकें, जिससे उच्चतर शिक्षा के उम्मीदवारों के लिए वित्तीय बाधाओं को कम किया जा सके। वर्ष 2024-25 में, पोस्ट-मैट्रिक और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले 95 लाख से अधिक छात्रों को लगभग 10,913 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति मिली है। इन योजनाओं में यह परिकल्पना की गई है कि किसी भी योग्य और मेधावी छात्र को वित्तीय तंगी के कारण शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए। परिणामस्वरूप, उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2014-15 में 23.7 की तुलना में वर्ष 2022-23 (अनंतिम) में बढ़कर 29.5 हो गया है।

(घ): सरकार विदेशी छात्रों के नामांकन की सुविधा के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क (जीआईएएन), अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएआरसी), भारत में अध्ययन आदि जैसी कई पहलों का कार्यान्वयन कर रही है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) निर्देशित पहलों से क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (क्यूएस डब्ल्यूयूआर) सहित अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। क्यूएस डब्ल्यूयूआर 2026 में 54 भारतीय संस्थानों को स्थान दिया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल भारतीय एचईआई की संख्या पिछले पांच वर्षों में दोगुनी हो गई है, जो क्यूएस डब्ल्यूयूआर 2021 में 27 से बढ़कर क्यूएस डब्ल्यूयूआर 2026 में 54 हो गई है, इस प्रकार निरंतर नीतिगत पहल, मजबूत अनुसंधान और नवाचार क्षमता और भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली की लगातार बढ़ती वैश्विक प्रोफ़ाइल को रेखांकित करती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया 2026 में भारत का दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, जिसमें 294 विश्वविद्यालय हैं, जो वर्ष 2025 में 163 से ऊपर हैं और शीर्ष 100 में 7 संस्थान हैं। वर्ष 2025 के लिए क्यूएस विषय रैंकिंग में 79 भारतीय एचईआई शामिल थे, जो पिछले वर्ष के 69 से 10 की वृद्धि है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में भारत की रैंकिंग भी वर्ष 2020 में 48 से आगे बढ़ गई है और वर्तमान में वर्ष 2025 में 38वें स्थान पर है।

*****